वी. रामास्वामी, सीजे और जी. आर. मजीठिया, जे. के समक्ष।

नगर समिति, भिवानी, - ☒ पीलकर्ता।

बनाम

मुंशी और ☒ न्य,-प्रतिवादी।

1983 का पत्र पेटेंट ☒ पील संख्या 394

31 मई 1989.

पंजाब नगर सुधार ☒ धिनियम, 1922 (हरियाणा में लागू) -एस. 44ए-की वैधता-योजना के निष्पादन के लिए ☒ वधि का विस्तार देने वाला प्रावधान-समय के विस्तार के लिए निर्धारित दिशानिर्देश-ऐसे प्रावधान-क्या इसे मनमाना कहा जा सकता है।

माना गया कि पंजाब नगर सुधार ☒ धिनियम, 1922 (जैसा कि हरियाणा में लागू है) की धारा 44ए का प्रावधान वैध है और इसके तहत की गई राज्य सरकार की कार्रवाई भी वैध है।

(पैरा 17)

माना गया कि यदि निर्धारित ☒ वधि के भीतर योजना क्रियान्वित नहीं होती है तो राज्य सरकार इस संतुष्टि पर इसे क्रियान्वित करने के लिए समय बढ़ा सकती है कि निर्धारित ☒ वधि के भीतर योजना को क्रियान्वित करना ट्रस्ट के नियंत्रण से बाहर है। ☒ धिकार का प्रयोग करने के दिशा-निर्देश प्रावधान में ही उल्लिखित हैं। यदि सामग्री मौजूद है तो राज्य सरकार की कार्रवाई को ☒ नुचित नहीं कहा जा सकता। न्यायालय द्वारा सामग्री की जांच निष्पक्ष रूप से

यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं की जा सकती है कि क्या यह सरकार के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थी कि ट्रस्ट निर्धारित ☒ वधि के भीतर योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकता है। सामग्री मौजूद नहीं थी या रिकॉर्ड नहीं था और राज्य सरकार उस सामग्री के आधार पर इस संतुष्टि पर पहुंची कि योजना को निर्धारित समय या विस्तारित समय के भीतर निष्पादित करना ट्रस्ट के नियंत्रण से बाहर था। यह मामला ☒ धिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि से संबंधित है और ☒ दालतें इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं कर सकती हैं। एक बार जब सामग्री मौजूद हो जाती है, जिसका उपयोग राज्य द्वारा संतुष्टि पर पहुंचने के लिए किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य की कार्रवाई मनमानी है।

(पैरा 16).

1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 19 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के 14 फरवरी, 1983 के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट के खंड एक्स के तहत लेटर पेटेंट ☒ पील; प्रार्थना करते हुए कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए, रिट याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए।

☒ पीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ ☒ धिवक्ता ए. एस. नेहरा और ☒ धिवक्ता जे. एस. दुहान।

एस. सी. मोहंता, ए. जी. हरियाणा के साथ एस. एस. ☒ हलावत डी. ए. जी. हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

निर्णय

जी. आर. मजीठिया, जे,

(1) 1983 के एल.पी.एल.पी. क्रमांक 394, 395, £396 और सी 442 9 को एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है क्योंकि इसमें कानून और तथ्य का सामान्य प्रश्न शामिल है।

(2) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विचार के लिए एकमात्र प्रश्न, हरियाणा में लागू पंजाब नगर सुधार ☒धिनियम, 1922 की धारा 44-ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित है (संक्षेप में "☒धिनियम")) और योजना को पूरा करने के लिए ☒वधि का विस्तार देने वाली उक्त धारा के प्रावधान के तहत समय-समय पर ☒धिसूचना जारी की जाती है।

(3) संक्षिप्त रूप से शामिल प्रश्न की सराहना के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि, ☒धिसूचना संख्या 7111-3सीआई-76/22899 दिनांक 7 जुलाई 1978 के तहत, हरियाणा के राज्यपाल ने ☒धिनियम स्वीकृत विकास योजना संख्या 23 की धारा 41(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए भिवानी सुधार ट्रस्ट द्वारा उक्त ☒धिनियम की धारा 28 की धारा 24 के साथ पढ़ी गई उपधारा 2 के तहत तैयार की। जैसा कि ☒धिनियम की धारा 42 की उप-धारा (1) में कहा गया है, योजना को भी ☒धिसूचित किया गया था। ☒धिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के तहत ☒धिसूचना जारी होने की तारीख से पांच साल की ☒वधि के भीतर योजना निष्पादित नहीं की गई थी। ☒धिसूचना संख्या 14/36/3सीआई-80 दिनांक- 13 ☒क्टूबर, 1980 के माध्यम से, हरियाणा के राज्यपाल ने योजना के कार्यान्वयन की ☒वधि 7 जुलाई, 1981 से 6 जुलाई, 1984 तक तीन साल की ☒वधि के लिए बढ़ा दी।

(4) राज्य सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन की ☒ वधि बढ़ाने की कार्रवाई से व्यथित व्यक्तियों ने इस न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से इसे चुनौती दी। 14 फरवरी, 1983 को इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाओं को ☒ नुमति दी गई थी। नगरपालिका समिति, भिवानी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर पेटेंट ☒ पील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद नगरपालिका समिति ने विशेष ☒ नुमति याचिकाएं दायर करके शीर्ष न्यायालय के समक्ष ☒ पील की। इन्हें 5 मार्च, 1987 के एक आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया गया: -

"हमने इन सभी ☒ पीलों में पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। हम उच्च न्यायालय के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं कि इन मामलों में शामिल योजनाओं को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा ***राधे शाम गुप्ता और ☒ न्य बनाम हरियाणा राज्य और ☒ न्य***[1] मामले में दिए गए कारणों के आधार पर रद्द किया जा सकता है। इसलिए, हम उन निर्णयों को रद्द करते हैं जिनके खिलाफ ये ☒ पीलें दायर की गई हैं और मामलों को केवल पंजाब नगर सुधार ☒ धिनियम, 1922 की धारा 44-ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में भेज देते हैं, जैसा कि हरियाणा में लागू है और उक्त धारा के परंतुक के तहत समय-समय पर जारी की गई ☒ धिसूचनाएं, जिनमें विचाराधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए ☒ वधि

---

[1] **ए.आई.आर. 1982 पंजाब और हरियाणा 519.**

का विस्तार दिया गया है। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष कोई ☒न्य प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। रिट याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला है कि यदि उन्हें सलाह दी जाए तो वे उपरोक्त प्रश्न तक सीमित ☒ तिरिक्त दलीलें दाखिल कर सकते हैं। उत्तरदाताओं के लिए उच्च न्यायालय में ☒ तिरिक्त प्रति-शपथपत्र दायर करना भी खुला है। उच्च न्यायालय छह महीने के भीतर रिट याचिकाओं का निपटारा करेगा। जब तक उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं का निपटारा नहीं कर देता तब तक कब्जे के संबंध में आज की स्थिति बरकरार रहेगी।

तदनुसार ☒ पीलों का निपटारा किया जाता है। शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार पार्टियों द्वारा ☒ तिरिक्त दलीलें दायर की गईं। विस्तारित ☒ वधि की समाप्ति पर, - 13 ☒ क्टूबर 1980 की ☒ धिसूचना के माध्यम से, हरियाणा राज्य ने - 3 जुलाई 1983 की ☒ धिसूचना के माध्यम से, योजना के कार्यान्वयन की ☒ वधि को जुलाई 7 1984 से जुलाई 6 1986 तक दो साल की ☒ वधि के लिए बढ़ा दिया। 2 जुलाई 1986 को योजना के क्रियान्वयन की ☒ वधि को 7 जुलाई 1986 से 6 जुलाई 1988 तक दो वर्ष की ☒ वधि के लिए और बढ़ा दिया गया। हरियाणा राज्य ने 4 जुलाई, 1988 की विस्तृत ☒ धिसूचना संख्या 14/36/80-iii सी की ☒ वधि 6 जुलाई, 1991 तक बढ़ा दी। ☒ धिनियम की धारा 44 की शक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन के लिए समय को ☒ निश्चित काल तक बढ़ाने के लिए ☒ नियंत्रित और निरंकुश शक्ति देता है। ☒ धिसूचनाओं की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी

गई थी कि इन्हें बिना दिमाग लगाए जारी किया गया था और राज्य सरकार के पास योजना के कार्यान्वयन के लिए समय के विस्तार को उचित ठहराने वाली कोई सामग्री नहीं थी।

(5) ☒ धिनियम का ☒ ध्याय IV ☒ धिनियम के तहत योजनाओं से संबंधित है। ☒ धिनियम की धारा 22 सामान्य सुधार योजना या पुनर्निर्माण योजना से संबंधित है। ☒ धिनियम की धारा 24 विकास और विस्तार योजनाओं से संबंधित है। ट्रस्ट को ☒ पने स्थानीय क्षेत्र में निहित नगरपालिका सीमा के भीतर "एक विकास योजना" तैयार करने का ☒ धिकार है। धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत, ट्रस्ट ट्रस्ट के स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रचार के लिए "एक विस्तार योजना" तैयार कर सकता है। और उसके निकटवर्ती किसी भी इलाके में नगर पालिका के विकास को नियंत्रित करने और उसके विस्तार के लिए प्रावधान करने के लिए ☒ धिनियम की धारा 24 की उप-धारा (3) "एक विकास योजना" में विकसित किए जाने वाले इलाके के लेआउट का प्रावधान करती है या "एक विस्तार योजना"। ☒ धिनियम की धारा 25 आवास आवास योजना से संबंधित है और ☒ धिनियम की धारा 26 पुनर्वास योजना से संबंधित है। पुन: आवास योजना उन व्यक्तियों को आवास प्रदान करने के लिए है जो ☒ धिनियम के तहत किसी भी योजना के कार्यान्वयन से विस्थापित हो गए थे या विस्थापित होने की संभावना थी। धारा 27 में यह प्रावधान है कि जब एक आवासीय घर का मालिक, जो इस ☒ धिनियम के तहत किसी भी योजना के कार्यान्वयन से विस्थापित होने की संभावना है, ट्रस्ट को पुनर्निर्मित करने के लिए आवेदन कर सकता है और इस ☒ धिनियम के तहत कोई भी योजना तब तक क्रियान्वित नहीं की जाएगी जब तक कि धारा 26

के तहत प्रदान की गई आवास योजना पूरी न हो जाए। ☒ धिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के तहत यह प्रावधान है कि ☒ धिनियम के तहत एक योजना को एक या ☒ धिक प्रकार की योजनाओं या उसकी किसी विशेष सुविधाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। धारा 28 की उपधारा (2) उन मामलों का प्रावधान करती है जिनका योजना बनाते समय ध्यान रखना होता है। धारा 29 ट्रस्ट को राज्य सरकार की मंजूरी के साथ सड़क संरेखण के लिए प्रावधान करने में सक्षम बनाती है और नगरपालिका समिति के पास योजना की सीमा के भीतर सड़क के लिए एक नियमित लाइन निर्धारित करने की शक्ति नहीं होगी और ऐसी सीमाओं के भीतर समिति द्वारा पहले से निर्धारित ऐसी कोई भी लाइन सड़क की नियमित लाइन या ☒ ग्रभाग की लाइन नहीं रहेगी। ☒ धिनियम की धारा 30 ट्रस्ट को सड़क संरेखण से सटे भवनों को पीछे या आगे स्थापित करने का ☒ धिकार देती है। ☒ धिनियम की धारा 31 किसी व्यक्ति को ट्रस्ट की ☒ नुमति के बिना योजना में शामिल इलाके में किसी भी इमारत को खड़ा करने, दोबारा बनाने, जोड़ने या बदलने से रोकती है। धारा 32 विलंबित सड़क योजना से प्रभावित संपत्ति के ☒ धिग्रहण से संबंधित है।स्थगित सड़क योजना में शामिल इलाके में, ट्रस्ट द्वारा निर्धारित सड़क संरेखण से प्रभावित किसी भी संपत्ति का मालिक राज्य सरकार द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किसी भी समय ट्रस्ट को नोटिस दे सकता है कि वह ऐसी नोटिस की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले ऐसी संपत्ति का ☒ धिग्रहण कर ले और ट्रस्ट तदनुसार संपत्ति का ☒ धिग्रहण करेगा। धारा 33 नगरपालिका समिति द्वारा या ☒ न्यथा किए गए आधिकारिक ☒ भ्यावेदन पर ☒ धिनियम के तहत

एक योजना की तैयारी से संबंधित है। ☒ धिनियम की धारा 34 के तहत, ट्रस्ट को ☒ धिनियम की धारा 33 के तहत किए गए प्रत्येक आधिकारिक प्रतिनिधित्व पर विचार करने और यह तय करने का आदेश दिया गया है कि ☒ धिनियम के तहत एक योजना तुरंत तैयार की जानी चाहिए या नहीं। धारा 35 ☒ धिनियम के तहत सुधार योजनाएं तैयार करते समय विचार किए जाने वाले मामलों से संबंधित है। ☒ धिनियम की धारा 36 में प्रावधान है कि जब ☒ धिनियम के तहत एक योजना तैयार की गई है, तो ट्रस्ट निम्नलिखित बताते हुए एक नोटिस तैयार करेगा: -

(i) तथ्य यह है कि योजना तैयार की गई है,

(ii) योजना में शामिल इलाके की सीमाएं, और

(iii) वह स्थान जहां ☒ धिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का विवरण और योजना में शामिल इलाके के सामान्य मानचित्र सहित योजना का विवरण उचित समय पर निरीक्षण किया जा सकता है।

☒ धिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) ट्रस्ट को धारा 36 की उप-धारा (1) में उल्लिखित नोटिस को आधिकारिक राजपत्र और समाचार पत्र या समाचार पत्रों में उस ☒ वधि के विवरण के साथ प्रकाशित करने का आदेश देती है जिसके भीतर आपत्तियां प्राप्त होंगी। नोटिस की एक प्रति नगर निगम समिति को भी भेजनी होगी। धारा 36 की उपधारा (3) ☒ ध्यक्ष को ☒ धिनियम की धारा 74 के तहत नियमों द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किसी भी आवेदक को धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (iii) में उल्लिखित सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करने का आदेश देती है। ☒ धिनियम के तहत योजना पर आपत्तियां दर्ज करने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो, तो दस्तावेजों

की जांच की जा सकती है। धारा 37 के □ंतर्गत □ धिनियम की धारा 36 के खंड (बी) के □ंतर्गत जिस नगरपालिका समिति को नोटिस भेजा गया है, वह नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर □ पना □ भ्यावेदन भेज सकता है। धारा 38 उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस जारी करने का प्रावधान करती है जो □ चल संपत्ति के मालिक हैं जो ट्रस्ट द्वारा योजना के कार्यान्वयन में प्रस्तावित या संभावित है। धारा 39 नगरपालिका समिति को उस इलाके से संबंधित सभी जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश देती है जिसके संबंध में धारा 36 के तहत एक नोटिस प्रकाशित किया गया है जैसा कि नगरपालिका रिकॉर्ड में उपलब्ध है, नियमों द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर। □ धिनियम की धारा 40 के तहत धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (ए), धारा 37 और धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (बी) के तहत □ धिनियम के तहत किसी भी योजना के संबंध में निर्धारित □ वधि की समाप्ति के बाद , ट्रस्ट को आपत्तियों, □ भ्यावेदन पर विचार करने और सभी आपत्तियों या □ भ्यावेदन पर विचार करने के बाद और उन व्यक्तियों को सुनवाई का □ वसर देने के लिए नियुक्त किया गया है जो सुनना चाहते हैं। यह योजना को छोड़ सकता है या संशोधन के साथ या बिना संशोधन के योजना को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकता है। राज्य सरकार की □ नुमति के बिना कोई भी योजना नहीं छोड़ी जा सकती।□ धिनियम की धारा 40 (2) उन दस्तावेजों से संबंधित है जिन्हें योजना की मंजूरी के लिए आवेदन के साथ □ ग्रेषित किया जाना है। धारा 40 की उपधारा (3) के तहत जब कोई योजना □ नुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है, तो ट्रस्ट आधिकारिक राजपत्र और समाचार पत्र या समाचार पत्रों

में लगातार दो सप्ताह तक एक नोटिस प्रकाशित करेगा कि योजना धारा 40 की उपधारा 1 के तहत ⊠ नुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है। धारा 41 राज्य सरकार को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के योजना को मंजूरी देने या योजना को मंजूरी देने से इनकार करने या पुनर्विचार के लिए ट्रस्ट को वापस करने का ⊠ धिकार देती है। यदि किसी योजना को धारा 41 की उप-धारा (1) के तहत पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है, और ट्रस्ट द्वारा संशोधित किया गया है, तो इसे ⊠ धिनियम की धारा 36 के ⊠ नुसार पुनः प्रकाशित करना होगा, ऐसे मामलों में जहां संशोधन योजना में शामिल इलाके की सीमाओं को प्रभावित करता है या किसी ऐसी भूमि का ⊠ धिग्रहण शामिल है जिसे पहले से ⊠ धिग्रहित करने का प्रस्ताव नहीं है, हर दूसरे मामले में, राज्य सरकार योजना के पुनर्प्रकाशन से छूट दे सकती है। उपधारा (1) के ⊠ंतर्गत धारा 42 के ⊠ नुसार, राज्य सरकार को सूचित करना होगा कि एक योजना स्वीकृत की गई है। धारा 42 की उपधारा (2) धारा 42 की उपधारा (1) के तहत जारी ⊠ धिसूचना में कुछ हद तक मिलीभगत का संकेत देती है। ⊠ धिनियम की धारा 43 के तहत, सरकार द्वारा योजना की मंजूरी और उसके कार्यान्वयन के बीच किसी भी समय ट्रस्ट द्वारा योजना की सीमा में बदलाव किया जा सकता है। धारा 4 (ए) के तहत, राज्य सरकार पहले से स्वीकृत किसी योजना को रद्द कर सकती है। जितने भी इलाकों के संबंध में ट्रस्ट ने इस ⊠ धिनियम के तहत एक योजना बनाई है या तैयार करने का प्रस्ताव किया है, उसे धारा 44 के प्रावधान के ⊠ नुसार एक संयुक्त योजना में शामिल किया जा सकता है। ⊠ धिनियम की धारा 44-ए समय सीमा निर्धारित करती है जिसके दौरान धारा 42 के ⊠ नुसार

स्वीकृत और ⊠धिसूचित एक योजना ट्रस्ट द्वारा निष्पादित की जाएगी। यदि कोई योजना ⊠धिसूचना की तारीख से पांच साल की ⊠वधि के भीतर क्रियान्वित नहीं की जाती है, तो यह ⊠पना कानूनी मूल्य खो देती है। धारा 44 के परंतुक द्वारा एक ⊠पवाद बनाया गया है जो राज्य सरकार को ⊠पने विवेक से धारा 44-ए के तहत प्रदान की गई ⊠वधि को बढ़ाने में सक्षम बनाता है यदि वह संतुष्ट है कि निर्धारित ⊠वधि के भीतर स्वीकृत योजना को निष्पादित करना ट्रस्ट के नियंत्रण से बाहर था।

(6) वैधानिक प्रावधानों का संक्षिप्त सारांश इंगित करता है कि ट्रस्ट द्वारा योजना तैयार करने के लिए क़ानून में एक पूर्ण और व्यापक प्रावधान किया गया है। ट्रस्ट को योजना को मंजूरी देने के लिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सभी आपत्तियों को सुनना होगा। योजना प्रस्तुत किए जाने के बाद राज्य सरकार मामले की नए सिरे से जांच करती है। यदि जांच करने पर राज्य सरकार को पता चलता है कि योजना को मंजूरी देना सार्वजनिक हित में नहीं है, तो वह इसे ⊠स्वीकार कर सकती है या पुनर्विचार के लिए ट्रस्ट को भेज सकती है। जैसा कि पहले देखा गया है, योजना ⊠पनी मंजूरी के बाद ⊠ंतिम रूप लेती है और ⊠धिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत ⊠धिसूचना जारी करना एक निर्णायक सबूत है कि योजना को विधिवत तैयार किया गया है और मंजूरी दी गई है। एक योजना ⊠धिसूचित होने के बाद किसी भी प्रक्रियात्मक प्रावधान का ⊠नुपालन न करने वाले को ठीक कर दिया जाता है। भूमि मालिक या प्रभावित व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सुनवाई का ⊠वसर मांग सकते हैं। उनकी आपत्तियों को ट्रस्ट द्वारा सुना और

निपटाया जाता है और उसके बाद ⊠ धिनियम की धारा 40 (2) में उल्लिखित सभी परिशिष्टों के साथ योजना राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि उनके पास योजना पर आपत्ति करने का कोई ⊠ वसर नहीं था। उनके पास एक ⊠ धिकार था जिसका वे लाभ उठा सकते थे या उठा चुके थे। योजना को विधिवत मंजूरी और ⊠ धिसूचित होने के बाद, इसे निर्धारित ⊠ वधि के भीतर क्रियान्वित किया जाना है। यदि किसी भी स्थिति में, ट्रस्ट निर्धारित ⊠ वधि के भीतर योजना को क्रियान्वित नहीं कर पाता है, तो राज्य सरकार इसके कार्यान्वयन की ⊠ वधि बढ़ा सकती है। विस्तार केवल इस संतुष्टि पर दिया जाता है कि यह ट्रस्ट के नियंत्रण से परे था कि वह ⊠ धिनियम की धारा 44 के तहत निर्धारित ⊠ वधि के भीतर या विस्तारित ⊠ वधि के भीतर योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका। -किसी भूमि मालिक या प्रभावित व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा उस ⊠ वधि को बढ़ाने से पहले सुनवाई का ⊠ वसर दिए जाने का कोई ⊠ धिकार नहीं है जिसके भीतर ट्रस्ट द्वारा योजना को क्रियान्वित किया जाना है। मामला पूरी तरह से राज्य सरकार और ट्रस्ट के बीच का है।

(7) श्री आनंद स्वरूप, विद्वान वरिष्ठ ⊠ धिवक्ता, जो योजना से प्रभावित कुछ भूस्वामियों की ओर से पेश हुए, ने प्रस्तुत किया कि योजना के कार्यान्वयन की ⊠ वधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को ⊠ नियंत्रित और निरंकुश शक्ति प्रदान की गई है। और ⊠ पनी दलील के समर्थन में, उन्होंने

<u>बेरियम केमिकल्स लिमिटेड और ☒न्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड और ☒न्य</u> [2], और ***<u>रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एस.डी. ☒ग्रवाल और ■☒न्य (3)</u>*** [3] का हवाला दिया। उसमें दिए गए कानून के प्रस्ताव के संबंध में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन सवाल तत्काल मामले के तथ्यों पर इसकी प्रयोज्यता का है।

(8) बेरियम केमिकल्स लिमिटेड मामले (सुप्रा) में, कंपनी ☒धिनियम की धारा 237 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। कंपनी ☒धिनियम की धारा 237 (बी) के तहत, केंद्र सरकार को किसी कंपनी के मामलों की जांच के लिए एक या ☒धिक सक्षम व्यक्तियों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए ☒धिकृत किया गया था। कंपनी ☒धिनियम की धारा 237 (ए) का खंड (ii) न्यायालय को यह घोषित करने के लिए ☒धिकृत करता है कि कंपनी के मामलों की जांच केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने पाया कि कंपनी ☒धिनियम की धारा 237 वैध थी और 'कंपनी लॉ बोर्ड को एक राय बनानी थी कि क्या एक इंस्पेक्टर द्वारा कंपनी की जांच का आदेश दिया जाए या नहीं और यह राय व्यक्तिपरक है और इसे प्रकट किए गए आधारों पर बनाया जाना चाहिए।

---

[2] ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 295.

[3] ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 707.

(9) बेरियम केमिकल्स लिमिटेड मामले में दिए गए फैसले का रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले (सुप्रा) में पालन किया गया। इन दोनों निर्णयों का ⊠नुपात तत्काल मामले के तथ्यों पर दूर-दूर तक लागू नहीं होता है। राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन की ⊠वधि तभी बढ़ाती है जब वह संतुष्ट हो जाती है कि किसी योजना को निर्धारित ⊠वधि के भीतर या विस्तारित ⊠वधि के भीतर निष्पादित करना ट्रस्ट के नियंत्रण से बाहर था।

(10) श्री बी.एस. गुप्ता, वरिष्ठ ⊠धिवक्ता, ने (*1) **श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ और ⊠न्य[4] , (2) स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ[5] , का उल्लेख किया। (3) बलदेव सिंह और ⊠न्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और ⊠न्य[6] , (4) उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड और दूसरा बनाम श्रम न्यायालय, यू.पी., कानपुर और दूसरा[7] और (5) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा बनाम ब्रोजो नाथ गैन्कुली और दूसरा[8] ।***

(11) मेनका गांधी के मामले में (सुप्रा), उनका पासपोर्ट सार्वजनिक हित में जब्त कर लिया गया था और भारत सरकार ने सार्वजनिक हित में पासपोर्ट जब्त करने के कारणों का खुलासा करने से इनकार कर दिया। भारत संघ के आदेश को संविधान के ⊠नुच्छेद 32 के तहत कई आधारों पर

---

[4] (4) ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 597.

[5] (1981) आई.एस. सी.सी. 664

[6] ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1239.

[7] ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1451.

[8] ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 1571.

चुनौती दी गई थी। इसी संदर्भ में शीर्ष न्यायालय ने पासपोर्ट ☒ धिनियम की धारा 10(3)(सी) की संवैधानिक वैधता पर विचार किया और यह माना गया कि यह निरर्थक है क्योंकि इसने मनमानी शक्ति प्रदान की है क्योंकि इसने पासपोर्ट जब्त करने से पहले पासपोर्ट धारक को सुनवाई का ☒ वसर प्रदान नहीं किया है। इस निर्णय की तत्काल मामले के तथ्यों पर दूर-दूर तक लागू नहीं है। ऊपर बताए गए कारणों से, इस मामले में प्रभावित पक्षों को राज्य सरकार द्वारा योजना को ☒ नुमोदन के लिए ☒ ग्रेषित करने से पहले ट्रस्ट द्वारा सुनवाई का ☒ वसर दिया गया था और राज्य सरकार ने इसे मंजूरी देने से पहले मामले की फिर से जांच की थी।

(12) स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम, यूनियन ऑफ इंडिया (सुप्रा) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की ☒ वधारणा से संबंधित है। यहां पहले बताए गए कारणों से, इस निर्णय का मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

(13) बलदेव सिंह का मामला (सुप्रा) कुछ क्षेत्रों को ☒ धिसूचित क्षेत्र समिति में शामिल करने से संबंधित है। इस फैसले का भी मौजूदा मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है।

(14) उ.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड का मामला (सुप्रा) पूर्ववर्ती कानपुर विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड में काम करने वाले एक कर्मचारी से संबंधित था, जिसने बोर्ड द्वारा कंपनी का ☒ धिग्रहण करने के बाद यूपी राज्य विद्युत बोर्ड में ☒ वशोषण का विकल्प चुना था। कर्मचारी को बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम के तहत सेवानिवृत्त किया गया था। विनियमन के संदर्भ में उन्हें सेवानिवृत्त करने की बोर्ड की कार्रवाई को वैध माना गया।

(15) केंद्रीय ⊠ंतर्देशीय जल परिवहन निगम मामले (सुप्रा) में तथ्य इस प्रकार थे: केंद्रीय ⊠ंतर्देशीय जल परिवहन निगम एक सरकारी कंपनी थी और इसे रखरखाव के सहायक कार्य के साथ नदी सेवा को बनाए रखने और चलाने के लिए 22 फरवरी, 1967 को स्थापित किया गया था। , विभिन्न आकारों और विवरणों के जहाजों का निर्माण करना, विभिन्न आकारों और विवरणों के जहाजों की मरम्मत करना और सामान्य इंजीनियरिंग गतिविधियाँ करना। "रिवर्स स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड" नामक कंपनी नदी सेवा के रखरखाव और संचालन सहित वही व्यवसाय कर रही थी जो निगम कर रहा था। उक्त कंपनी और निगम के बीच एक व्यवस्था योजना पर हस्ताक्षर किये गये। उक्त कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन निगम को किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी या कर्मचारियों की वैध आपत्ति के ⊠ धीन जितना संभव हो सके मौजूदा कर्मचारियों और श्रमिकों को लेना था। जिन कर्मचारियों को निगम द्वारा नहीं लिया जा सका, उन्हें ⊠ंतरणकर्ता कंपनी द्वारा कानून के तहत देय सभी धनराशि और औद्योगिक विवाद ⊠ धिनियम के तहत या ⊠ न्यथा कानूनी रूप से स्वीकार्य सभी वैध और कानूनी मुआवजे का भुगतान किया जाना था। ब्रोजो नाथ गांगुली नाम के एक व्यक्ति कंपनी में काम कर रहे थे कि व्यवस्था की योजना के तहत उनकी सेवाएं निगम ने ले लीं और उन्हें उप मुख्य लेखा ⊠ धिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तरूण कांति सेनगुप्ता भी कंपनी में कार्यरत थे और उनकी सेवाएं महाप्रबंधक के रूप में ली गई थीं। इन कर्मचारियों के रोजगार के नियम और शर्तें नियुक्ति पत्रों में शामिल थीं, लेकिन इन्हें निगम द्वारा बनाए गए सेवा नियमों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। उनकी

सेवाएं समाप्त कर दी गईं और कर्मचारियों ने संविधान के ⊠ नुच्छेद 226 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके निगम की कार्रवाई पर हमला किया और उनकी सेवाओं की समाप्ति और उस नियम को भी चुनौती दी जिसके तहत कार्रवाई की गई थी। नियम को सार्वजनिक नीति के विपरीत बुरा पाया गया क्योंकि इसने निगम को तीन महीने का नोटिस देकर या इस तरह के नोटिस के बदले में तीन महीने का वेतन और महंगाई भत्ता देकर, किसी भी मामले में, स्थायी कर्मचारी के रोजगार को समाप्त करने का ⊠ धिकार प्रदान किया। यहां भी, हम यह समझने में विफल हैं कि इस फैसले की तत्काल मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता कैसे है। वह नियम जो निगम को तीन महीने के वेतन के भुगतान पर एक स्थायी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने में सक्षम बनाता था, उसे निरर्थक घोषित कर दिया गया क्योंकि यह मनमानी और ⊠ नुचितता से ग्रस्त था। मौजूदा मामले में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

(16) श्री के.पी. भंडारी, वरिष्ठ ⊠ धिवक्ता, जो याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए भी उपस्थित हुए, ने ***सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर और ⊠ धीक्षक, निवारक सेवा सीमा शुल्क, कलकत्ता और ⊠ न्य बनाम चरण दास मल्होत्रा***[9], पर भरोसा किया जो सीमा शुल्क ⊠ धिनियम की धारा 124 (ए) के तहत जब्ती का नोटिस देने की ⊠ वधि बढ़ाने की कलेक्टर की शक्ति से संबंधित है। सीमा शुल्क ⊠ धिनियम की धारा 110 तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी से संबंधित है। धारा 110

[9] (9) ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 689.

की उपधारा (2) में प्रावधान है कि जहां उपधारा (1) के तहत कोई माल जब्त किया जाता है और माल की जब्ती के छह महीने के भीतर धारा 124 के खंड (ए) के तहत उसके संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, सामान उस व्यक्ति को लौटाया जाना था जिसके कब्जे से वे जब्त किए गए थे। धारा 110 में एक प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत सीमा शुल्क कलेक्टर पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर छह महीने से ⊠धिक की ⊠वधि के लिए ⊠वधि नहीं बढ़ा सकता था। एक्सटेंशन दिए गए लेकिन पीड़ित पक्ष को कोई नोटिस दिए बिना। शीर्ष न्यायालय ने पाया कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर ही विस्तार दिया जा सकता है और इसमें समय विस्तार देने के लिए पर्याप्त कारण निर्धारित करने के लिए कलेक्टर द्वारा की गई जांच शामिल है। सीमा शुल्क ⊠धिनियम की धारा 110 के तहत, सामान को छह महीने की समाप्ति के बाद उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए जिसके कब्जे से उन्हें जब्त किया गया था और यदि सामान छह महीने के भीतर वापस नहीं किया जाना है। पर्याप्त कारण पर ⊠वधि बढ़ाई जानी चाहिए और इसमें कलेक्टर द्वारा मामले की जांच शामिल है। इस निर्णय की वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी कोई प्रयोज्यता नहीं है। जैसा कि पहले देखा गया है, योजना ⊠धिसूचित होने के बाद, यह ⊠ंतिम रूप ले लेती है और सरकार योजना को ⊠धिसूचित करने से पहले यह सुनिश्चित करती है कि योजना के निर्माण से संबंधित क़ानून के ⊠निवार्य प्रावधानों का विधिवत ⊠नुपालन किया गया है। किसी क़ानून को उचित वर्गीकरण की परीक्षा पास करनी होती है, लेकिन विधायी या कार्यकारी कार्रवाइयाँ मनमाने ढंग से होने पर ख़राब घोषित की जा सकती हैं। चुनौती वाले

प्रावधान में कोई मनमानी नहीं है. राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन की ⊠ वधि बढ़ा सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ट्रस्ट ⊠ पने नियंत्रण से परे कारणों से निर्धारित ⊠ वधि के भीतर योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका। हमने रिकॉर्ड की जांच की है और हमने पाया है कि जब राय बनी थी तब सामग्री राज्य सरकार के समक्ष मौजूद थी। सामग्री ⊠ प्रासंगिक नहीं थी और इसे राज्य सरकार द्वारा योजना को क्रियान्वित करने के लिए विस्तार देने की सिफारिश करने वाली राय बनाने के लिए पर्याप्त माना गया था। वर्तमान मामले में, रिट याचिकाएं 1982 में दायर की गई थीं और रिट-याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने पर रोक लगाने का आदेश प्राप्त किया गया था। उच्च न्यायालय और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में लंबी मुकदमेबाजी के मद्देनजर, ट्रस्ट योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका और मामले की परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा योजना को क्रियान्वित करने की ⊠ वधि बढ़ाना उचित था। प्रारंभ में, योजना को ⊠ धिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत ⊠ धिसूचित होने की तारीख से पांच साल की ⊠ वधि के भीतर क्रियान्वित किया जाना था। यदि निर्धारित ⊠ वधि के भीतर योजना क्रियान्वित नहीं होती है, तो राज्य सरकार इस संतुष्टि पर कि योजना को निर्धारित ⊠ वधि के भीतर क्रियान्वित करना ट्रस्ट के नियंत्रण से बाहर है, कार्यान्वयन के लिए समय बढ़ा सकती है। ⊠ धिकार का प्रयोग करने के दिशा-निर्देश प्रावधान में ही उल्लिखित हैं। यदि सामग्री मौजूद है तो राज्य सरकार की कार्रवाई को ⊠ नुचित नहीं कहा जा सकता। न्यायालय द्वारा सामग्री की जांच निष्पक्ष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं की जा सकती है कि क्या यह सरकार के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त

थी कि ट्रस्ट निर्धारित ☒ वधि के भीतर योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकता है। जैसा कि पहले देखा गया था, सामग्री रिकॉर्ड पर मौजूद थी और राज्य सरकार उस सामग्री के आधार पर इस संतुष्टि पर पहुंची कि निर्धारित समय के भीतर या विस्तारित समय के भीतर योजना को निष्पादित करना ट्रस्ट के नियंत्रण से परे था। यह मामला ☒ धिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि से संबंधित है और ☒ दालतें इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं कर सकती हैं। एक बार जब सामग्री मौजूद हो जाती है, जिसका उपयोग राज्य द्वारा संतुष्टि पर पहुंचने के लिए किया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य की कार्रवाई मनमानी है।

(17) इस प्रकार, हम मानते हैं कि ☒ धिनियम की धारा 44-ए का प्रावधान वैध है और इसके तहत राज्य सरकार की कार्रवाई भी वैध है।

(18) परिणामस्वरूप, ☒ पीलें स्वीकार की जाती हैं। हालाँकि, हम पार्टियों को उनकी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ते हैं।

एस.सी.के.

☒ स्वीकरण : स्थानीय भाषा में ☒ नुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह ☒ पनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी ☒ न्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का ☒ंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा